दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, रविवार 23 जून 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 266

महत्वपूर्ण एवं खास

ईडी को फिर मिला नोटों का पहाड़, जमीन कारोबारी के घर से 1 करोड़ कैश और 100 जिंदा कारतूस बरामद

रांची (आरएनएस)। झारखंड के रांची में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की टीम ने आज जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के चेशायर होम रोड और कांके के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने कमलेश के घर पर जमीन घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज खंगाले। छानबीन के क्रम में उसके कांके स्थित आवास से एक करोड़ रुपया नगद, एक पिस्तौल और 100 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ईडी की टीम बरामद रुपयों के संबंध में उससे पूछताछ कर रही है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले ईडी ने कमलेश को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन समन जारी होने के बावजूद वह जवाब देने के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुआ। ज्ञातव्य है कि ईडी की टीम जमीन घोटाले मामले में अब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

गुरुग्राम: फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण विस्फोट, नौ लोगों की मौत; कई मलबे में दबे

गुरुग्राम (आरएनएस)। गुरुग्राम के दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक फैक्ट्री में शनिवार सुबह जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में नौ व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दर्जनों मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बॉयलर फटने से हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस और फायर बिग्रेड की टीम मौजूद है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं, ब्लास्ट के बाद फायर ब्रिगेड की 10 गाडिय़ां मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम की ओर से रेस्क्यू किया जा रहा है। बता दें कि यह हादसा शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे हुआ था। फायरबॉल बनाने की फैक्ट्री में धमका हुआ था। उस फैक्ट्री के साथ लगती दो और फैक्ट्री भी आग की चपेट में आ गए। बचाव कार्य करने के दौरान अभी भी छोटे धमाके हो रहे हैं।

गैंगस्टर छोटा शकील के रिश्तेदार आरिफ शेख की आर्थर रोड जेल में मौत, दाऊद का भी था करीबी

मुंबई (आरएनएस)। गैंगस्टर छोटा शकील के रिश्तेदार आरिफ शेख उर्फ आरिफ भाईजान की मुंबई के जेजे अस्पताल में दिल का दौरा पडऩे से मौत हो गई। वह आर्थर रोड जेल में बंद था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2022 में टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में शेख (61) को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दाऊद इब्राहिम और छोट शकील सहित दाऊद गैंग के कई सदस्य शामिल हैं। शेख गिरफ्तारी के बाद आर्थर रोड जेल में बंद था और जेजे अस्पताल में ही उसका इलाज चल रहा था। बता दें कि जुलाई 2023 में ठाणे जिले से सटे मीरा रोड एरिया में शेख की प्रॉपर्टी को एनआईए ने जब्त कर लिया था। बता दें कि आरिफ अबूबकर शेख को टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उस पर टेरर फंडिंग के अलावा हथियारो की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप थे। शेख और उसके भाई मोहम्मद सलीम कुरैशी को सलीम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है।

भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि की करेंगे समीक्षा, बांग्लादेशी नागरिकों को इलाज के लिए ई-वीजा का ऐलान

नई दिल्ली । आरएनएस

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत और बंगलादेश गंगा जल संधि की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं और बंगलादेश से चिकित्सा के लिए भारत आने वालों के लिए ई-वीजा की सुविधा दी जाएगी।

मोदी ने विकास कार्यों में भारत का सबसे बड़ा भागीदार बताते हुए कहा कि बंगलादेश के साथ अपने संबंधों को भारत अत्यधिक प्राथमिकता देता है। भारत की दो दिन की यात्रा पर नयी दिल्ली आयीं बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद एक साझा संवादाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हसीना की इस माह यहां की दूसरी यात्रा है। वह मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी आयी थीं।

उन्होंने बताया कि दोनों देश डिजिटल प्रौद्योगिकी, समुद्र और अंतरिक्ष क्षेत्र की पहलों और रक्षा उत्पादन तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार पर सहमत हुए हैं। मोदी ने बंगलादेश के संस्थापक राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बंगलादेश के सपने को साकार करने में, भारत के सहयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2026 में बंगलादेश 'अल्प विकसित' देश की श्रेणी से निकल कर 'विकासशील देश' बनने जा रहा है। उन्होंने बंगलादेश की इस प्रगति में हसीना के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, 'सोनार बंगला' को नेतृत्व देने के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का अभिनन्दन करता हूँ। हसीना के साथ संबंधों की प्रागढ़ता को रखांकित करते हुए मोदी ने कहा, 'पिछले लगभग एक वर्ष में, हम दस

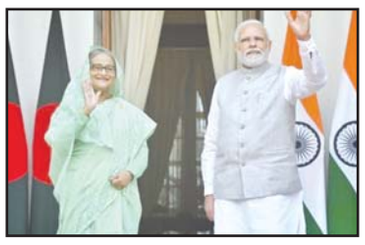

बार मिले हैं। लेकिन आज की मुलाकात विशेष है, क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधान मंत्री शेख हसीना जी हमारी पहली राजकीय अतिथि हैं।

मोदी ने कहा, बंगलादेश हमारी 'सबसे पहले पड़ोसी' पॉलिसी, पूर्व के देशों के साथ काम करने की नीति पॉलिसी, ' सागर ' (क्षेत्र में सभी देशों के लिए सुरक्षा और समृद्धि) और एशिया प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत से सपने और पहल के संगम पर स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत और बंगलादेश ने पिछले एक ही वर्ष में साथ मिल कर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं को पूरा किया है।इस संबंध में उन्होंने अखौड़ा से अगरतला के बीच भारत-बंगलादेश के बीच छठे सीमा-पारीय रेल मार्ग सम्पर्क, खुलना-मोंगला बंदरगाह से भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए मालवहन सुविधा, मोंगला बंदरगाह को रेल से जोडऩे की परियोजना तथा 1320 मेगावाट क्षमता के मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स से बिजली उत्पादन शुरू किए जाने का उल्लेख किया।

मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच अब भारतीय रुपये में व्यापार की शुरुआत भी हो चुकी है।भारत-बंगलादेश के बीच, गंगा नदी पर, दुनिया की सबसे लंबी नीदी क्रूज सेवा को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।भारत-बंगलादेश के बीच पहली सीमापारीय मैत्री गैस पाइपलाइन भी पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय ग्रिड से होते हुए, नेपाल से बंगलादेश तक बिजली निर्यात, ऊर्जा क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय सहयोग का पहला उदाहरण बना है। मोदी ने कहा, एक ही वर्ष में, इतने सारे क्षेत्रों में, इतने बड़ी-बड़ी पहलों को जमीन पर उतारना, हमारे संबंधों की स्पीड और स्केल (गति और विस्तार) को दर्शाता है।

मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री हसीना की इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए भविष्यदर्शी रुप रेखा तैयार की है। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में दोनों पक्षों के बीच ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकॉनमी, स्पेस जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है और इस सहमति का लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा। मोदी ने कहा, भारत बंगलादेश 'मैत्री उपग्रह' हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगी। हमने संपर्क सुविधा, वाणिज्य और सहयोग को अपनी सोच के केंद्र में रखा है। पिछले दस वर्षों में हमने 1965 से पहले की संपर्क सुविधाओं को दोबारा खड़ा कि कर दिया है।

उन्होंने कहा, अब हम और अधिक डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी पर बल देंगे। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति मिलेगी।हमारे आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, दोनों पक्ष सीपा पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि बंगलादेश के सिराजगंज में एक स्थलीय कंटेनर डिपो के निर्माण के लिए भारत समर्थन देगा। मोदी ने दोनों देशों के बीच नदी जल क्षेत्र में सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच 54 नदियाँ साझा है, ये भारत और बंगलादेश को जोडती हैं। दोनों देश बाढ़ से निपटने, स्थिति की पूर्व चेतावनी , पेयजल परियोजनाओं के क्षेत्र में आपस में सहयोग करते आए हैं।

महिला डॉक्टर को जालसाजों ने बनाया शिकार, 5 दिन में लगाई 1 करोड़ 30 लाख रुपए की चपत

नोएडा । आरएनएस

यूपी के गौतमबुद्ध नगर से हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। नोएडा के सेक्टर-49 में रहने वाली एक महिला डॉक्टर को जालसाजों ने अपना शिकार बनाया। उन्होंने 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर डॉक्टर के बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 30 लाख रुपये ठग लिए। साइबर क्राइम की इस घटना को अंजाम देने के लिए ठगों ने बाकायदा जाल बुना।

एसीपी साइबर विवेक रंजन के अनुसार, महिला डॉक्टर के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉलर ने खुद को नार्को टेस्ट विभाग का अधिकारी बताते हुए कहा कि आपका पार्सल मुंबई एयरपोर्ट से जब्त किया गया है और उसमें अवैध दस्तावेज के साथ 5 किलो ड्रग्स है। इस संबंध में आपको पूछताछ के लिए या तो मुंबई आना होगा या फिर आपको स्काइप लिंक भेजते हैं, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए।

पीड़िता को बताया गया कि उनके आधार कार्ड पर 6 खाते चल रहे हैं, जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। महिला डॉक्टर को डरा धमका कर दबाव बनाया गया, जिसके चलते वो अगले 5 दिनों तक स्काइप के जरिए जालसाजों से जुड़ी रहीं। इस बीच ठगों ने डॉक्टर के बैंक खाते से 1 करोड़ 30 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद पीड़ित महिला ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस स्टेशन में कराई। साइबर क्राइम पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। कॉलर के मोबाइल नंबर और बैंक खाता संख्या की सहायता से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर अपराधियों की तलाश में जुट गई है।

नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, झारखंड से 6 लोगों को हिरासत में लिया

रांची । आरएनएस

नीट (यूजी) पेपर लीक मामले के तार झारखंड के हजारीबाग, रांची और देवघर से भी जुड़ गए हैं। बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओयू) ने शनिवार को देवघर शहर से इस मामले में छह लोगों को हिरासत में लिया। ये सभी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं, जो देवघर में किराए के मकान में छिपकर रह रहे थे।

बिहार पुलिस की टीम ने हजारीबाग में भी नीट (यूजी) के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों की जांच की है। बताया जा रहा है कि लीक हुए पेपर का सॉल्वर गैंग रांची और हजारीबाग

से ऑपरेट कर रहा था। देवघर शहर से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसमें सींटू नामक युवक भी शामिल है। उसके साथ पांच अन्य लोग यहां पिछले कुछ दिनों से मजदूर बनकर टिके हुए थे। बिहार ईओयू की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। पेपर लीक में इनकी क्या भूमिका है, इस बारे में फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

ईओयू की अब तक की जांच में पेपर लीक के मास्टरमाइंड के रूप में सिकंदर यादवेंदु नामक जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है, वह लंबे समय तक रांची में रहकर ठेकेदारी करता था। रांची स्थित मेडिकल कॉलेज रिम्स के एक कॉटेज में वह अनधिकृत तरीके से रहता था। उसने रिम्स में भी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के छोटे-मोटे काम ठेकेदारी पर कराए थे। उसने कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा था और बाद में वह किसी तरह बिहार के दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के तौर पर बहाल हो गया, लेकिन रांची में उसके कनेक्शन बरकरार रहे।

सूत्रों के मुताबिक, सिकंदर ने रांची और हजारीबाग में सॉल्वर गैंग का नेटवर्क बना रखा था। लीक हुए पेपर इसी गैंग के लोगों ने सॉल्व कर व्हाट्सएप पर भेजे और इसके बाद चुनिंदा परीक्षार्थियों को उत्तर रटवाए गए। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के जिन नंबरों से पेपर और उनके जवाब का आदान-प्रदान किया गया, उनके सिम फर्जी नाम से खरीदे गए थे। काम होने के बाद सभी सिम नष्ट कर दिए गए।

पेपर लीक पर 10 साल की कैद, एक करोड़ तक जुर्माना; देश में देर रात लागू हुआ कानून

नई दिल्ली । आरएनएस

पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकना है।

इस साल फरवरी में संसद से यह कानून पारित हुआ था, जो 21 जून 2024 से प्रभाव में आ गया है। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी (नकल) पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्रस्ताव है और पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई संगठित अपराध करता है, जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, सेवा प्रदाता, या कोई अन्य संस्थान शामिल है, तो उन्हें कम से कम 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

कानून कहता है कि जुर्माना 1 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा। किसी संस्थान के संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाए जाने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान कानून में है और परीक्षा की लागत भी उस संस्थान से वसूली जाएगी। हालांकि, यह कानून परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को दंडात्मक प्रावधानों से बचाता है। अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी।

कानून'अनुचित साधनों' को, पेपर या आंसर की लीक करना, अनधिकृत संचार के माध्यम से परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या अन्य उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना, प्रॉक्सी उम्मीदवार बैठाना (किसी सॉल्वर को कैंडीडेट की जगह परीक्षा में बैठाना), फर्जी परीक्षा आयोजित कराना, परीक्षा सूची या रैंक को लेकर नकली दस्तावेज जारी करना और योग्यता दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के रूप में परिभाषित करता है।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर-जमानती हैं। डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) या एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) रैंक का अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के पास किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर-आधारित परीक्षाएं इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।

नहीं रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित, लंबी बीमारी के बाद निधन

अयोध्या । आरएनएस

अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया है। लक्ष्मीकांत दीक्षित (86 वर्षीय) लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। लक्ष्मीकांत दीक्षित वाराणसी के मीरघाट स्थित सांगवेद महाविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना काशी नरेश के सहयोग से की गई थी। आचार्य लक्ष्मीकांत की गिनती काशी में यजुर्वेद के बड़े विद्वानों में होती थी। लक्ष्मीकांत दीक्षित पूजा पद्धति में भी सिद्धहस्त माने जाते थे। लक्ष्मीकांत दीक्षित ने वेद और अनुष्ठानों की दीक्षा अपने चाचा गणेश दीक्षित भट्ट से ली थी। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के जेऊर के रहने वाले लक्ष्मीकांत दीक्षित का परिवार कई पीढ़ियों पहले काशी में आ कर बस गया था। उनके पूर्वजों ने नागपुर और नासिक रियासतों में भी धार्मिक अनुष्ठान कराए हैं. लक्ष्मीकांत के बेटे इसे पहले सुनील दीक्षित ने बताया था कि उनके पूर्वजों ने ही शिवजी महाराज का राज्याभिषेक भी करवाया था।

छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए आर्थिक सहायता का किया आग्रह

- राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता की राशि पूर्व की तरह रखा जाए : ओपी
- राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार का रखा प्रस्ताव
- खनिज समृद्ध ज़िलों के आस पास के क्षेत्रों में विकास के लिए डीएमएफ के नियम में बदलाव का किया आग्रह
- इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टेक्सटाइल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क के स्थापना का भी किया अनुरोध
- बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ने रखे राज्यहित के कई प्रस्ताव

नई दिल्ली । आरएनएस

बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने राज्यों को विशेष सहायता की राशि, स्टेट कैपिटल रीजन के विकास व राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार सहित राज्यहित के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव व सुझाव रखे। दिल्ली के भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री उपस्थित रहे।बैठक में राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना की। साथ ही उन्होंने देश में अधोसंरचना निर्माण, कौशल संवर्द्धन, उद्यमिता विकास, और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, और जनसुविधाओं के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की भी प्रशंसा की है।राज्यहित के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता के रूप में वर्ष 2020-21 से 50 वर्षों के लिये ब्याज रहित ऋण राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अंतरिम बजट 2024-25 में इस योजना के लिये गत वर्ष के समान ही 1,30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, किन्तु पार्ट-1 अंतर्गत गत वर्ष के प्रावधान 1 लाख करोड़ को कम करते हुए 55,000 करोड़ ही रखा गया है। उन्होंने इस योजना के लिए पूर्व की तरह राशि के प्रावधान का अनुरोध किया।बैठक में स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत बताते हुए चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर अटल नगर को देश के सबसे सुनियोजित एवं ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य के सीमित संसाधनों से सडक़, पेयजल, विद्युत सुविधा, आवास तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है, किन्तु नई राजधानी को रायपुर तथा दुर्ग-भिलाई के साथ मिलाकर एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में आधुनिक नगरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जाना है।उन्होंने इसे सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, बैंकिंग और ग्रीन एनर्जी के हब के रूप में विकसित करने के लिए बजट में पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की। राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार की मांग करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि

छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण खदानों से खनिज का परिवहन पर्याप्त रेल नेटवर्क के अभाव में अधिकांशत: सडक़ मार्ग से होता है।

रेल द्वारा माल एवं यात्री परिवहन सडक़ मार्ग की तुलना में सस्ता होने एवं औद्योगिक विकास के लिए कारण रेल नेटवर्क का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने राज्य में रेल सुविधाओं के विस्तार कार्यों की स्वीकृति का अनुरोध किया।

बैठक में वित्तमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की एक भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं गुजरती है। उन्होंने नागपुर-रायपुर-विशाखापटनम नवीन इंडस्ट्रियल कॉरीडोर विकसित करने अथवा वर्तमान प्रस्तावित कॉरिडोर से रायपुर को जोडऩे की जरूरत बताई।इसके अलावा उन्होंने राज्य में टेक्सटाइल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना का भी अनुरोध किया।वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत दुर्गम वन क्षेत्रों में निर्मित सडक़ों के संधारण हेतु बजट में प्रावधान करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा केंद्रीय सुरक्षा बलों के कैंपों तक सडक़ निर्माण के लिए भी बजट में प्रावधान किया जाए।वित्तमंत्री ने रायपुर में वृद्धजनों के लिए इंटीग्रेटेड जिरियाट्रिक हेल्थ सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत बच्चों के लिए खाद्य सामग्री की दर और रसोइयों के मानदेय में वृद्धि का आग्रह किया। इसके साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत प्रीमियम राशि में वृद्धि करने की मांग की।ओपी चौधरी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सातवें वेतनमान लागू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार का 50 प्रतिशत केंद्रान्श की मांग की। वहीं उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया।

ओपी चौधरी ने डीएमएफ के नए नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए डीएमएफ (जिला खनिज निधि) नियमों के अनुसार, डीएमएफ का उपयोग केवल खदान क्षेत्र के 15 किमी के भीतर या खदान से 25 किमी तक की दूरी पर रहने वाले लोगों पर ही किया जा सकता है।

पहले के नियमों के तहत, डीएमएफ का 75% तक धनराशि उसी जिले में खर्च की जा सकती थी जिसमें खदान स्थित है, जबकि शेष 25% धनराशि पास के जिलों में भी खर्च की जा सकती थी। छत्तीसगढ़ में हाल के वर्षों में कई नए जिलों का गठन हुआ है, जिससे आसपास के जिलों में विकास कार्यों के लिए डीएमएफ के धन को मिलाकर आवश्यकता के आधार पर खर्च करने की अधिक जरूरत है। लेकिन नए डीएमएफ नियम इस पर प्रतिबंध लगाते हैं।